महिंदर सिंह सुल्लर की अदालत के समक्ष, **जे.**

हार्डविंदर सिंह,-अपीलार्थी

बनाम

परमजीत सिंह और अन्य उत्तरदाता

आर. एस. ए. 2007 का No.85

28 जुलाई, 2011

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-धारा 11,96 और 100-अपीलकर्ता का अधिकार-अपीलकर्ता की प्राप्ति-अपीलकर्ताकर्ता पहली अपीलकर्ता में निष्कर्ष से व्यथित है-प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादी ने विवादित निर्णय को चुनौती नहीं दी-आयोजित, किसी में भी अपीलकर्ता करने का अधिकार-केवल निष्कर्ष के खिलाफ कोई अपीलकर्ता दायर नहीं की जा सकती है-सी. पी. सी. की धारा 96 और 100 डिक्री के खिलाफ अपीलकर्ता प्रदान करती है न कि निर्णय।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1974 के ए. आई. आर. सर्वोच्च न्यायालय के मामले में बाई बनाम विजय कुमार और अन्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति में नागरिक प्रकृति का मुकदमा लाने का अंतर्निहित अधिकार है और जब तक कि मुकदमा अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं है, तब तक कोई अपनी पसंद का मुकदमा ला सकता है।इसकी रखरखाव के लिए एक मुकदमा के लिए अधिनियम के किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है और यह पर्याप्त है कि कोई भी क़ानून मुकदमा को प्रतिबंधित नहीं करता है।लेकिन अपीलों के संबंध में स्थिति बिल्कुल विपरीत है।अपील का अधिकार किसी में भी नहीं है और इसलिए, इसकी रखरखाव के लिए अपील को कानून का स्पष्ट अधिकार होना चाहिए और कोई भी अपील केवल इस सरल कारण से निष्कर्ष के खिलाफ नहीं हो सकती है कि संहिता ऐसी किसी भी अपील के लिए प्रावधान नहीं करती है।

(पैरा 13)

आगे आयोजित अभिनिर्धारित किया कि प्रथम अपील न्यायालय ने अभियोक्ता के मुकदमा को ऊपर वर्णित तरीके को खारिज कर दिया है, इसलिए प्रति अभियोक्ता संख्या 5 में से एक द्वारा दायर नियमित दूसरी अपील कानूनी रूप से विचारणीय नहीं है, जिसे एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

(पैरा 15)

अरुण जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, Mr.Jaivir S.Chandail के साथ, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

(699)

कंवलजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, Mr.Harmanjit सिंह,

अधिवक्ता, प्रतिवादी Nos.1 से 3 के लिए।

V.S.Rana, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए।

प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से विशाल दीप गोयल, अधिवक्ता

महेंद्र सिंह सुल्लार, जे। (मौखिक)

सटीक रूप से, प्रासंगिक तथ्य, जिनका मुख्य विवाद को तय करने के सीमित उद्देश्य के लिए, तत्काल अपील की स्थिरता और रिकॉर्ड से निकलने वाले प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, वे हैं कि शिव सिंह-प्रतिवादी के बेटे सरबजीत सिंह (इसके बाद "वादी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने विवादित भूमि के संबंध में अपने हिस्से की सीमा तक कब्जे की डिक्री के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें वसीयत, यदि कोई हो, तो प्रतिवादी के मुकदमा में Nos.1 से 4, अवैध, अमान्य, स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ, अपनी मां Smt.Parkash कौर (प्रतिवादी संख्या 1), भतीजे-परमजीत सिंह, मनदीप सिंह और सुख को रोक दिया।

(2) अभियोक्ता द्वारा स्थापित मामला, जहां तक प्रासंगिक है, संक्षेप में, यह था कि उसके पिता शिव सिंह के हाथों में मुकदमा भूमि, पैतृक सह-मुकदमीय और संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति थी।उन्होंने अपने भाइयों-प्रतिवादी Nos.5 और 6 के साथ अपने पिता और माता के साथ एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन किया।इसलिए, वे सभी सह-मालिक होने के नाते भूमि के कब्जे में थे।हालाँकि, प्रतिमुकदमी Nos.1 से 4 ने कुछ जाली वसीयत के आधार पर जबरन और अवैध रूप से मुक़दमे की भूमि पर कब्जा कर लिया है।वसीयत को अवैध, अमान्य बताया गया था।उपरोक्त आरोपों के आधार पर, अभियोक्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ कब्जे की डिक्री और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है।

(3) प्रतिद्वंद्वी प्रतिअभियोक्ता Nos.1 से 4 ने अभियोक्ता के दावे का खंडन किया और लिखित बयान दायर किया, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, अभियोक्ता की कुछ प्रारंभिक आपत्तियों, मुकदमे की स्थिरता, वाद हेतुक और अधिस्थिति का अनुरोध करते हुए।मुक़दमे की ज़मीन को स्व-अर्जित संपत्ति होने का मुकदमा किया गया था।

शिव सिंह, जिनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने स्वेच्छा से उनके पक्ष में 06.07.1989 दिनांकित पंजीकृत वसीयत को निष्पादित किया था। इसलिए, उनकी मृत्यु के बाद, वे इंगित पंजीकृत वसीयत के अनुसरण में मुकदमा भूमि के मालिक और कब्जे में आ गए।

(4) हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 5 ने वाद में निहित अभिवचनों की पंक्ति को ध्यान में रखते हुए अपना अलग लिखित बयान दायर किया, हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 6 ने अपना अलग लिखित बयान दायर किया जिसमें कहा गया कि मुकदमे की भूमि उसके पिता शिव सिंह के हाथों में स्व-अर्जित संपत्ति है, जिन्होंने स्वेच्छा से प्रतिवादी के मुकदमा में पंजीकृत वसीयत को निष्पादित किया।यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि प्रतिद्वंद्वी प्रतिमुकदमियों ने मुकदमा में निहित अन्य सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और मुकदमे को खारिज करने के लिए प्रार्थना की है।

(5) ट्रायल कोर्ट ने अभियोक्ता के मुकदमे का फैसला सुनाया और विमुकदमित फैसले और डिक्री दिनांक 30.04.2003 के माध्यम से 06.07.1989 की वसीयत को अमान्य घोषित कर दिया।

(6) निचली अदालत के विमुकदमित फैसले से व्यथित होकर, परमजीत सिंह, मंदीप सिंह और हरजिंदर सिंह के बेटों, हरबरजिंदर सिंह ने प्रतिअभियोक्ता Nos.2 से 4 तक का मुकाबला करते हुए अपील दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और पहली अपील न्यायालय ने अभियोक्ता के मुकदमे को विमुकदमित फैसले और दिनांकित 11.10.2006 डिक्री के आधार पर खारिज कर दिया।

(7) वादी-सरबजीत सिंह और 4 और 6 तक प्रतिवादी का मुकाबला करने वाले ने स्वीकार किया और पहले अपील न्यायालय के विवादित फैसले को चुनौती नहीं दी।हालांकि, केवल हरदेविंदर सिंह-प्रतिवादी संख्या 5 ने इससे संतुष्ट महसूस नहीं किया और वर्तमान नियमित दूसरी अपील को प्राथमिकता दी, जिसे अंततः मेरे सामने रखा गया और इस तरह, मैं मामले से अवगत हूं।

(8) शुरुआत में, अपील के प्रस्ताव स्तर पर सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर केवल तत्काल नियमित दूसरी अपील की स्थिरता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है।

(9) स्थिति का सामना करते हुए, अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का एकमात्र तर्क कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर अपील बनाए रखने योग्य है, न तो मान्य है, न ही मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियां।

अर्जुन सिंह बनाम बचन सिंह और अन्य (1), बिल्कुल ही लागू हैं, और तथ्यों पर समाप्त करने योग्य, जिसमें यह देखा गया था कि भले ही मुख्य वाद खारिज कर दिया गया था, लेकिन मुकदमों के अधिकारों के संबंध में दर्ज किया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सी. पी. सी. की खंड 11 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा और अपीलार्थी (उसमें) को आगे की अपील के माध्यम से उस निष्कर्ष को चुनौती देने का अधिकार था।संभवतः, उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में कोई भी विवाद नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे लिए, यह तत्काल विवाद में अपीलकर्ता के बचाव में नहीं आएगा।

(10) जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है कि सभी संहितात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने और मुकदमों द्वारा अभिलेख पर लाए गए पूरे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने अभियोक्ता के मुकदमे का फैसला सुनाया और विवादित निर्णय और दिनांकित डिक्री के माध्यम से इंगित वसीयत को अमान्य घोषित कर दिया।प्रतिअभियोक्ता हरबरजिंदर सिंह के बेटों, परमजीत सिंह, मंदीप सिंह और सुखजिंदर सिंह द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया और अभियोक्ता के मुकदमे को पहली अपील न्यायालय ने विमुकदमित फैसले और दिनांकित डिक्री के माध्यम से खारिज कर दिया।

(11) ऊपर, अभिलेख पर स्थिति होने के कारण, अब इस मामले में निर्धारण के लिए जो एकमात्र प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या वर्तमान नियमित दूसरी अपील केवल प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर की गई है, वह विचारणीय है या नहीं?

(12) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए, जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक होगा।एक बार, अभियोक्ता का मुकदमा पहले अपील न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, तो मेरे विचार से, प्रतिअभियोक्ता संख्या 5 को विवादित डिक्री द्वारा संभवतः एक पीड़ित मुकदमाकार नहीं कहा जा सकता है और अभियोक्ता द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने के खिलाफ उसके द्वारा दायर अपील (प्रतिअभियोक्ता संख्या

5) कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है, जैसा कि इस संदर्भ में सी. पी. सी. की खंड 100 के तहत विचार किया गया है।

(13) यहाँ जो बात विवादित नहीं है, वह यह है कि केवल एक डिक्री द्वारा पीड़ित व्यक्ति (निष्कर्षों द्वारा नहीं) कानूनी रूप से अपील को बनाए रख सकता है।अपील का अधिकार अधिनियम का एक सृजन है और कोई भी अपील केवल निष्कर्ष के खिलाफ नहीं है।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बाई बनाम विजय कुमार और अन्य (2) मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति में,

(1) 2009 (2) पीएलआर 328

(2) एआईआर 1974 एससी 1126 703

(महिंदर सिंह सुलार, जे.)

सिविल प्रकृति का मुकदमा लाएं और जब तक कि मुकदमा अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं है, तब तक कोई अपनी पसंद का मुकदमा ला सकता है।इसकी रखरखाव के लिए एक मुकदमा के लिए अधिनियम के किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है और यह पर्याप्त है कि कोई भी क़ानून मुकदमा को प्रतिबंधित नहीं करता है।लेकिन अपीलों के संबंध में स्थिति बिल्कुल विपरीत है।अपील का अधिकार किसी में भी नहीं है और इसलिए, इसकी रखरखाव के लिए अपील को कानून का स्पष्ट अधिकार होना चाहिए और कोई भी अपील केवल इस सरल कारण से निष्कर्ष के खिलाफ नहीं हो सकती है कि संहिता ऐसी किसी भी अपील के लिए प्रावधान नहीं करती है।

(14) एक बार फिर, एक समान प्रश्न का निर्णय लिया गया बनारसी और अन्य बनाम राम फाल (3) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सी. पी. सी. की धारा 96 और 100 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, यह (पैरा 8) निम्नानुसार शासित किया गया थाः-

“सी. पी. सी. की धारा 96 और 100 प्रत्येक मूल डिक्री या अपील में पारित प्रत्येक डिक्री से क्रमशः अपील करने का प्रावधान करती है; किसी भी प्रावधान में उस व्यक्ति की गणना नहीं की गई है जो अपील दायर कर सकता है।हालाँकि, यह निर्णयों के एक लंबे समूह द्वारा तय किया जाता है कि अपील दायर करने का हकदार होने के लिए व्यक्ति को डिक्री से व्यथित होना चाहिए।जब तक कोई व्यक्ति डिक्री से प्रतिकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होता है, वह अपील दायर करने का हकदार नहीं है।फूलचंद और एक अन्य वी. गोपाल लाल, 1967 (3) एस. सी. आर. 153; कंवर गोलचा बनाम मेसर्स गोलचा प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड, 1970 (3) एस. सी. सी. 573; बाई वी. विजय कुमार और अन्य, (1974) 2 एस. सी. सी. 393 देखें।केवल निष्कर्ष के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है।यह ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि सी. पी. सी. की धारा 96 और 100 दोनों डिक्री के खिलाफ अपील का प्रावधान करती हैं न कि फैसले के खिलाफ।”

(15) उपरोक्त कारणों के आलोक में, मेरे विचार से, जैसा कि प्रथम अपील न्यायालय ने अभियोक्ता के मुकदमे को खारिज कर दिया है, ऊपर वर्णित तरीके से, इसलिए, प्रतिअभियोक्ता संख्या 5 में से एक द्वारा दायर नियमित दूसरी अपील कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है, जिसे एतद्द्वारा मामले की प्राप्त करने वाली परिस्थितियों में खारिज कर दिया जाता है।

ए. एग्ग।

(3) ए. आई. आर 2003 एस. सी. 1989

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

gurvinder kaur